



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

मई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1991/फाल्गुन 13, 1912

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1991/PHALGUNA 13, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के काफ़ में
एक वा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

दिल्ली राज्यालय
(आधिकारिक कार्यविधान)

(बजट प्रभार)

अधिसूचना

मई दिल्ली, 4 मार्च 1991

फा.सं. 15/(81) दो (डी)/91

बजट

1991-92

(प्रत्यक्षित)

वित्त मन्त्री

श्री यशवन्त निन्हा

का

सांख्य

4 मार्च, 1991

महोदय,

मैं इस वर्ष 1991-92 के लिए अन्तरिम बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस बजट को, जिसने सदाचार, 1990 के मध्य में कार्यवाच संभ ला था, एक संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति विरासत में भिन्नी थी। 1.30 नवम्बर 1990 को केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा 13,000 करोड़

रुपए के स्तर पर पहुँच गया था, जो राजस्व में कमी होने प्रीर खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण था। अर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले घाट महीनों के वीरान थोक की महत्व सूचकांक में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उपरोक्ता की महत्व सूचकांक में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भूगतान संतुलन की स्थिति में तेजी से गिरावट आने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत कमी आ गई जो नवम्बर, 1990 के बच्च में निरकर 3,142 करोड़ रुपए का रह गया और यह राशि एक महीने के वित्तपोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं थी।

3. ये घटनाएँ कोई दूसरीपूर्ण संयोग के कारण नहीं थीं, बल्कि वित्त में अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रबंध में विभिन्नों के कारण पैसा छुड़ा। ऐसा मैं न तो किसी उत्तराधी की भावना से प्रीर न ही वायित्व को टालने की इच्छा से कह रहा हूँ। परन्तु समय आ गया है कि सरकार अपनी वित्ताधीनों में संसद प्रांत लोगों को भागीदार बताए ताकि एक राष्ट्रीय गहरायि विकास हो सके, जिससे कि एक सामूहिक वायित्व के रूप में स्वस्थ अर्थव्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया जा सके।

4. आपक आर्थिक असंतुलन, जो आर्थिक प्रीर नियन्त्रण द्वारा है, इस संख्या का मूल कारण है। सरकार के राजनीतीय घाटे को देश में उधार ले कर पूरा करना पड़ा। अर्थव्यवस्था के कानू खाते के घाटे को अनिवार्यतः विदेश से उधार लेकर वित्तपोषित करना पड़ा। जो आंतरिक प्रीर विदेशी ऋण इकट्ठे हो गए हैं उनके परिपोषन का भार अब अत्यंत दूसर हो गया है। मेरे यह कहने की आवश्यकता नहीं है

कि तभी मरकार ग्राह न ही अर्थव्यवस्था नम्बे समय भक्त अपने साधनों से भास्त्र रह कर जीवित रह सकती है। उधार गणि लेवर अथवा उधार के समय में जीने की नीति को अब विकल्प गुजारात नहीं है। उदार विकल्प अब पूर्ण समाप्त हो चुके हैं।

5. यह कोई आव्याय को आन नहीं कि निरन्तर राजकोषीय असंतुलनों से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फोटिकार्ग वज्रों में बृद्धि हुई है और भूमतान मंतुलन पर बोस पड़ा है। इस प्रकार, अर्तमान विन वर्ष के प्रौद्योगिक में भी अर्थव्यवस्था पर एक अंतर्गत राजकोषीय संकट लाया रहा था। और भूमतान मंतुलन की स्थिति अर्थव्यवस्था की अनिवार्य। ये ममम्याण, तंत्र-संवेद और खाड़ी में यूद्ध व संकट के कारण आग अवरोधी के कारण और भी बढ़ गई। इसने राजकोषीय स्थिति में प्रियावट का अनुभव किया है। उपभोक्ताओं को दो-अंक-प मूद्रास्फोटिक का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को भूमतान मंतुलन के संकट का जामना करना पड़ रहा है। आने वाले वर्ष में खाड़ी पूर्ण तरह से अवाजा लगता कठिन है। उनके बाद अन्तर्राष्ट्रीय तेज़ क्रमते किस स्तर पर म्हिर होगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

6. कार्यभार समाजने पर हम ज्यादा इन्जार नहीं कर सकते थे और बजटाध स्थिति में प्रारंभिक भिरावट नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए, बोर्ड समय गंभीर, मैने अनिवार्य राजस्व जुटाने के अम्ले अंतर्क उपाय लाए किए। कर-अनुमानत प्रारंभ राजस्व प्रभावों में सुधार, करने के लिए कदम उठाए गए। खाचे पर अत्यधिक संभव कठार तिंब्रण लाए जिया गया। इसके साथ ही मैने संसद को यह आव्यासन भी दिया था कि सरकार राजकोषीय स्थिति को सुधूद बनाने को अन्यत प्राथमिकता देती है, चाहे इसके लिए हमें कठोर नियंत्रण लेने पड़े और कठिन विकल्प अपनाने पड़े, जिन्हे काफी समय में स्थिति रखा नहीं था। मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूंगा कि 1991-92 में राजकोषीय समावोधन के प्रति मेरी व्यवस्थाएँ बुढ़ी और अटप हैं।

7. कठिन परिस्थितियों में, जहां अनिवार्य हो जाता है, हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विकल्प नीति विकास करने हेतु कुछ प्रारंभ समय की आवश्यकता होती। बजट तैयार करने से हम यह मुनिश्वित करना चाहते हैं कि ऐसे व्यापक आव्यायिक समायोजन से विकास की प्रक्रिया की गति अवश्यक न हो और गर्भों पर बोसन पड़े। और भी अविक्षिक आवश्यकता हस बात को है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया एक मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है। हम एक विन्तन दृष्टिकोण तैयार करने के कार्य में जूटे हैं जिससे इन समस्याओं के मंतोजनक प्रारंभ स्थिति समावान का भाग प्रशस्त होगा। इसके लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सदन में महि 1991 में अप्र० 1991-92 का नियमित बजट प्रस्तुत होने वक्त प्रत्येक करने का आप्रत्र है।

वर्ष 1990-91 के लिए संशोधित अनुमान

8. अन्तर्रिम बजट प्रस्तुत करते समय, मैं प्रारम्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष के संबंध में संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त और देना चाहूंगा। वर्ष 1990-91 के बजट का कुल खर्च का संशोधित प्रनुमान 1,06,717 करोड़ रुपए है जो 94,535 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमानों की तुलना में पर्याप्त बृद्धि दर्शाता है। तथापि, एक समृद्धि तुलना की दृष्टि से, मूल बजट अनुमानों को 99,309 करोड़ रुपए तक समायोजित किया जाना चाहिए, जिसमें राजस्व सरकारों को लघु व्यवस्था अवृत्त और रेलवे के पूँजीगत खर्च का एक हिस्सा, जिसमें पहले प्राप्तियों में से अटाकर दिखाया गया था, शामिल करना होगा जिससे यह संशोधित अनुमानों के अनुरूप ही भकेगा। आनुपातिक प्राप्तियों द्वारा यह बृद्धि 4,100 करोड़ रुपए तक प्रतिमुत्तुनि हो जाएगी। इस प्रकार खर्च में निवास बृद्धि 3,308 करोड़ रुपए होगी। खर्च

में यह बृद्धि काफी सीमा तक, अर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वारा बजट के बाद को कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण है, जो मरकार के नियंत्रण से बाहर थी।

9. प्रधिक मात्रा में लघु व्यवस्था मंत्रियों को दिए गए अनिवार्य अनुमानों की राशि 2,270 करोड़ रुपए थी। इसके अनिवार्य अनुमान अनुमानों में राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके प्रारम्भिक धारों के एक भाग को पूरा करने के लिए लिए गए 521 करोड़ रुपए के अवृत्त भी शामिल हैं जबकि 966 करोड़ रुपए की राशि राज्यों के अवृत्त भी आवाने के लिए दी गई, जैसा कि नवीन विन आयोग ने सिफारिश की थी।

10. अब अदायगियां बजट अनुमानों की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए अधिक होगी। इस कमिकों के लिए वेश्वन की राशि 170 करोड़ रुपए अधिक होगी। कुवैत से भारतीय नामारकों की स्वदेश वापसी के कारण राजकोष पर 300 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित बोस पड़ेगा। ग्रामीण अवृत्त गहन योजना के लिए, जिसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, 500 करोड़ रुपए की राशि की ओर आवश्यकता होती। ईरनीकल कोडियों की राशि अनुमानों को तुलना में 800 करोड़ रुपए प्रधिक होगी, क्योंकि रुपया अदायगी अवृत्तस्था के अन्तर्गत व्यापार में अस्थायी प्रस्तुलन है। प्रमुख संविधियों के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 1,034 करोड़ रुपए अधिक हैं। खाद्य संविधियों में 250 करोड़ रुपए की बृद्धि चीनी के कारण है, जिसके संबंध में जनवरी, 1940 में उत्पादकों को दी गई तिरंगे कीमतों में बृद्धि की अनुमति के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रण कीमतों में कोई बृद्धि नहीं की गई। उर्वरक संविधियों में 400 करोड़ रुपए की बृद्धि का कारण, नेप्था की ओर, कीमतों में बृद्धि होना जबकि आवानित उर्वरकों को मगाने की लागतों में बृद्धि होती है। नियान संविधियों में 384 करोड़ रुपए की बृद्धि मूल्यानुमार दरों में दी गई नकद प्रतिपूनि समधेन के कारण है, यह नियान की रुपया लागत के कारक स्वतंत्र है।

11. सकल कर राजस्व 58,916 करोड़ रुपए होने की संभवता है जो 59,778 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 862 करोड़ रुपए कम है। अनुमान है कि प्रायकर और कपनी कर से बजट अनुमानों की तुलना में कमः 134 करोड़ रुपए और 261 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे जो मध्यपतः वर्तमान वर्ष के दौरान अनिवार्य मसाधन जुटाने के लिए बजट के बाद उठाए गए कदमों का परिणाम है। नथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान अनिवार्य मसाधन जुटाने के बास्ते बजट के बाद किए गए उपायों के बाबजूद सोमाशुलक और उत्पाद शुलक से बजट अनुमानों की तुलना में कमः 660 करोड़ रुपए और 625 करोड़ रुपए की कम राशि प्राप्त होने की संभवता है। कर-भिन्न राजस्व 419 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। अनुमान है कि पृथीग प्राप्तियों में 4,399 करोड़ रुपए का सुधार होगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए लघु व्यवस्था मंत्रियों से प्राप्त होंगे।

12. कुल प्राप्तियों और कुल खर्च के संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि वर्तमान वर्ष के अत में बजटीय घाटा 10,772 करोड़ रुपए का होगा, जबकि बजट के समय इसका अनुमान 7,206 करोड़ रुपए लगाया गया था। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यदि गजस्व और खर्च दोनों ही ओंतों में पिछले तीन महीनों में कुछ उपाय लागू नहीं किए जाते तो यह बजटीय घाटा काफी अधिक होता। यह जिना की बात है कि अतिरिक्त खर्च को प्रत्यधिक उधार लेकर पूरा करना पड़ा है, जिससे वर्तमान वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटा बढ़कर 43,331 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जबकि बजट में 36,795 करोड़ रुपए के घाटे की कल्पना की गई थी। राजकोषीय घाटे में वृद्धि कुछ सीमा तक सरकार के नियंत्रण से बाहर रही है, जिसका कारण लघु व्यवस्था में संशोधित अनुमानों में 2,270 करोड़ रुपए की बृद्धि हो गई। यदि यह कारण नहीं होता तो राजकोषीय घाटा, जिसका कर अनुमान सकल खर्च का 8,59 प्रतिशत होता है, सकल वरेलू उत्पाद का 8,14 प्रतिशत होता।

वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान

13. यह मैं वर्द 1991-92 के लिए अन्तर्रिम बजट के मवध में जिस कर्तव्य जो लेखानुदान के प्रयोगाधार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कि सरकार प्रधान वित्तीय वर्ष के पश्चले चार महीनों के दौरान अनियन्त्रित खर्च की गूँत कर पड़े। अनुदान की मात्रा और वार्षिक वित्तीय वित्तान को, जो पूरे वित्तीय वर्ष के मवध में है, नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय यथावत्यक स्तर से संशोधित और अन्तिम रूप दिया जाएगा।

14. इस समय 1991-92 में केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए बजटीय समयान की राशि 18,550 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि वर्ष 1991-92 के लिए गज़ों और संघ राज्य धोतों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय महायना की राशि 14,710 करोड़ रुपए रखी गई है। इस आधार पर जेंड्रोंग योजना के लिए परिव्यय की राशि 42,148 करोड़ रुपए और गज़ों तथा संघ राज्य धोतों की योजना परिव्यय की राशि, जिसमें विषेष धोत कार्यक्रम भी शामिल है, लगभग 29,300 करोड़ रुपए होगी। मेरा यह अप्राप्त रहा है कि निर्णयों और समाज के गीव लोगों के लिए कार्यक्रमों के वास्ते अधिकाधिक सम्बन्ध सहजाया प्रदान की जाए।

15. हमने गैर-योजना खर्च में किफायत बरतने और कम खर्च करने पर जोर दिया है, जिसमें कि निवेश के स्तर बनाए रखे जा सके और विकास को गति दी रहे। इस प्रकार, मैंने यह मुनिषित करने के लिए कार्य सांवधानों बढ़ायी है कि प्रधान वर्ष गैर-योजना खर्च न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। बास्तविक दृष्टि से, मुख्य गैर-योजना खर्च, जो वर्ष मान वर्ष में 76,761 करोड़ रुपए है, शास्त्र वर्ष मासूली रूप से बढ़कर 76,907 करोड़ रुपए हो जाएगा।

16. अगले वित्त वर्ष में देय होने वाली महाराष्ट्र भर्ते की अरिंगिन किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं भी मंत्रालयों और विभागों से यह प्रतिरोध कर रहा हूँ कि वे इस प्रतिशिव्वत देयान को, उपयुक्त बटोरियां करके, अपने-अपने बजट परिव्ययों में छपाएं। राज्यों को लघु अवधियों में उत्तर लिस्ट के लिए लोगों की प्रशासनों के वास्ते अगले वर्ष 4,500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है, जबकि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 6,770 करोड़ रुपए है। यह कठोरों गार्डों वित्त योजना को भारतीय बजट वेक की प्रस्तावित अनुसरण के कारण है, जिसकी स्थापना शीत्र ही की जाएगी।

17. अगले वर्ष के दौरान रक्षा खर्च के बास्ते 16,850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष प्रारम्भ की गई प्रारम्भ रक्षण राहगांयोजना के अन्तर्गत सरकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की जा रही है।

18. ग्रामीणीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के हमारे प्रयासों में यह आवश्यक है कि समिलियों से संबंधित व्यय को युक्तिमय बनाया जाए। इस दिशा में यहां कदम के तौर पर मैं, वर्ष 1990-91 के लिए संक्षेपित अनुमानों में निर्धारित, उर्वरक तथा आवश्यक पर्याप्त मिलियों के लिए यह 9,550 करोड़ रुपए के बजटीय ग्रामेण्टों की वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में घटाकर 8,616 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरे विचार से, निर्धारित और जहरनमांद लोगों के लिए समिलियों के बेहतर लक्ष्य रखने तथा साथ ही प्रबंध में सुधार करने से इन ग्रामेण्टों के भीतर ही वांछित उद्देश्यों को पूरा करना संभव हो सकेगा।

19. प्राप्तियों के क्षेत्र में, कराधान की मीजुदा दरों के अनुसार आगामी वर्ष में 6,354 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान में यह राशि 5,916 करोड़ रुपए है। आगामी वर्ष के लिए, करों में से राज्यों को उनके द्विसे का

प्राप्तियों करने के लिए 15,900 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 14,535 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, केंद्र की निवल राजस्व-प्राप्तियों, जिसमें कर्तव्यभित्र राजस्व भी शामिल है, जो वर्ष 1990-91 में 57,381 करोड़ रुपए थी वर्ष 1991-92 में बढ़कर 63,584 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पूजी-प्राप्तियों के अन्तर्गत, आगामी वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए के बाजार रक्षण लिए जाएंगे जो वर्तमान वर्ष के 8,000 करोड़ रुपए के बाजार रक्षण की तुलना में कम है। गार्डीय बचत योजना का प्रस्तावित तथे भारत बचत बैंक की अन्तरित किए जाने के कलमस्वरूप, वर्ष 1991-92 में लघु बचतों के निवल संग्रहों से 6,000 करोड़ रुपए की बजटीय प्राप्तियों होने का अनुमान है जबकि, इसकी तुलना में 1990-91 में यह राशि 8,000 करोड़ रुपए है। आगामी वर्ष में, अनुवानों के अन्वाचा, किन्तु वापसी प्राप्तियों को अद्याकर, 4,000 करोड़ रुपए की विदेशी महायना प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 3,984 करोड़ रुपए है।

20. यह निर्णय लिया गया है कि सरकार इतारा सांवंजनिक धोत के चुनौदों उपशमों में आवारा ईक्विटी का 20 प्रतिशत भाग विनिवेश करके उसे सरकारी धोत के वित्तीय व्यवधान संस्थानों और पारम्परिक निवियों में अन्तरित कर दिया जाए। यह विनिवेश, जिसमें ईक्विटी का प्राधार विस्तृत होता, प्रबंध को बेहतर बनाएगा तथा इन उदाहरणों के लिए संघीयों की उपलब्धता में बढ़िया करेगा तथा इसमें वर्ष 1991-92 में राजकोष को 2,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने का सभावना है। इस निर्णय को लाए करने संवेदी प्रदत्तियों के द्वारा, जिन्हें नियां दिया जा रहा है, अपना से वीचित किए जाएंगे।

21. प्राप्तियों और व्यय की अन्य विभिन्नाओं की दियावाल में लेने हुए, वर्ष 1990-91 की कर्तव्यों के अनुसार कुल 1,00,140 करोड़ रुपए की प्राप्तियों होने का अनुमान है तथा कुल व्यय 1,10,167 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, इस प्रकार, यन्त्रित संसाधन जटाए दिना, बजटीय घाटा 9,977 करोड़ रुपए का होगा।

22. आर्योजना व्यय तथा व्यय की व्यवस्था भी विभिन्न श्रेणियों के लिए बजटीय प्रावधानों में बढ़िया नियमित बजट में होने वाली कुल प्राप्तियों की मात्रा से सम्बन्धित है तथा उन पर निर्भर करती है। नियमित बजट वेश करने से पहले की अन्तरित व्यवधियों की उपर्योग व्यवस्था भवित्वान्तरों की आरीकी से जांच करने और समीक्षा करने के लिए किया जाएगा ताकि यह मुनिषित किया जा सके कि केंद्रीय सरकार का गतकोषीय घाटा वर्ष 1991-92 में सकल घेत्तु उत्पाद का लगभग 6,5 प्रतिशत रहे। इसलिए, आज आदायाधिकों, वेतन व्यवधा वेतन प्रदायियों और राज्य सरकारों को सांविधिक अनुवानों संबंधी मदों को छोड़कर, प्रावधानों में वृद्धि की, जहा कहीं भी यह पर्याप्त रूप से अधिक है, उस व्यवस्था के नियंत्रण के लिए, जिसके लिए लेखानुदान मांगा जा रहा है, पूरी तरह से हिताव में रही लिया जा सका है। मैं, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी धोत के उपर्योगों में अनुरोध कर रहा हूँ कि इस व्यवधि के दोगांशे में कोई नयी योजनाएँ शुरू न करें और न ही कोई नयी वर्डी वचनवद्धाएँ करें। सभी मंत्रालयों और विभागों की यह सलाह भी दी जाएगी कि वे अपने व्यवधि में व्यवधिक शिकायत बरतें तथा सादगी बरतता सरकार का एक आदर्श बना रहेंगे।

23. मैं दिन विशेषक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 1991-92 में आधारकर की मीजुदा दरों को जारी रखना है। सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। स्थानीय विशेषक के में, आगामी वित्तीय वर्ष के दोगांशे सीमा-शुल्क की महायना व्यवधि दरों की विशेषक की दरों से अद्याकर नहीं रखी गई है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1991

No. F. 15(81)|B(D)|91

BUDGET 1991-92

(Interim)

Speech of

SHRI YASHWANT SINHA

Minister of Finance

4th March, 1991

Sir,

I rise to present the interim Budget for the year 1991-92.

2. The new Government, which assumed office in mid-November 1990, inherited an economic situation of crisis proportions. The budget deficit of the Central Government reached a level of Rs. 13,000 crores, on 30th November 1990, as a consequence of revenue shortfalls and expenditure overruns. The Wholesale Price Index registered an increase of 8.5 per cent, while the Customer Price Index rose by 11.9 per cent during the first eight months of the current financial year. The sharp deterioration in the balance of payments situation led to a rapid depletion of foreign exchange reserves, which dropped to Rs. 3142 crores at the end of November 1990 and this sum was not even sufficient to finance imports for one month.

3. These developments were not an unfortunate coincidence, but were the outcome of shortcomings in the macro-management of the economy in the past. I say this neither in a spirit of acrimony nor with a desire to apportion blame. But the time has come for the Government to share its concerns with the Parliament and the people, in an endeavour to evolve a national consensus, so that the restoration of the health of the economy is perceived as a collective responsibility.

4. Macro-economic imbalances which have been large and persistent are at the root of the problem. The fiscal deficits of the Government had to be met by borrowing at home. The current account deficits of the economy were inevitably financed by borrowing from abroad. The burden of servicing the accumulated internal and external debt has now become onerous. I need hardly stress that neither the Government nor the economy can live beyond its means for long. The room for manoeuvre, to live on borrowed money or time, has been used up completely. The soft options have been exhausted.

5. It is not surprising that the persistent fiscal imbalances have accentuated inflationary pressures in the economy and strained the balance of payments. Thus, even at the beginning of the current financial year, the economy was in a serious fiscal crisis and faced a very

difficult balance of payments situation. These problems have been sharply exacerbated by the oil shock and the dislocations caused by the crisis and the war in the Gulf. We have experienced a deterioration in the fiscal situation. Consumers are faced with double digit inflation. The economy is faced with a balance of payments crisis. The impact of the Gulf war on the economy, in the year to come, is difficult to assess fully at this point of time. The level at which international oil prices would stabilise thereafter cannot be predicted.

6. On assumption of office, we could not have waited and allowed a further deterioration in the budgetary situation. Therefore, without losing any time, I introduced a package of measures to mobilise additional revenue. Steps were taken to improve tax compliance and revenue collections. The strictest possible control was exercised on expenditure. At the same time, I had also assured the Parliament that the Government attached a very high priority to fiscal consolidation, even if it meant hard decisions and difficult choices which had been postponed for long. I would like to stress, once again, that my commitment to fiscal adjustment in 1991-92 remains firm and irrevocable.

7. In the difficult set of circumstances, where the uncertainties remains, we shall need some more time to evolve a comprehensive strategy for restoring the health of the economy. In formulating the Budget, we want to ensure that such a macro-economic adjustment does not disrupt the rhythm of the growth process and does not place a burden on the poor. What is more, the process of fiscal correction needs to be situated in a medium term perspective. We are engaged in the formulation of a comprehensive approach which would provide a satisfactory and sustainable solution to these problems. This needs time. I would, therefore, plead with the House to wait until the regular Budget for 1991-92 is presented in May 1991.

REVISED ESTIMATES FOR 1990-91

8. In presenting the interim Budget, I would like being with a brief account of the Revised Estimates for the current financial year. The Revised Estimate of total expenditure for the Budget of 1990-91 is Rs. 1,06,717 crores which reflects a significant increase over the original Budget Estimate of Rs. 94,535 crores. For a more appropriate comparison, however, the original Budget Estimate should be adjusted to Rs. 99,309 crores, to include small savings loans to State Governments and a part of the capital expenditure of the Railways previously netted against receipts, which would make it consistent with the Revised Estimate. The increase would be off-set, to the extent of Rs. 4,100 crores, by matching receipts. Thus, the net increase in expenditure would be Rs. 3,308 crores. This expenditure overrun is attributable, in significant part, to some unexpected post-budget developments during the current financial year which were beyond the control of Government.

9. Additional loans to State Governments, following larger collections of small savings, account for Rs. 2,270 crores. In addition, the Revised Estimates also include loans of Rs. 521 crores to States to meet a part of their opening deficits with the Reserve Bank

of India, while another Rs. 966 crores has been provided to write-off loans to States as recommended by the Ninth Finance Commission.

10. Interest payments would be Rs. 1000 crores higher than the Budget Estimate. Pensions for defence personnel would be Rs. 170 crores more. The repatriation of Indian citizens from Kuwait would impose an unanticipated burden of Rs. 300 crores on the exchequer. The scheme of rural debt relief, which was not adequately provided for in the budget, would require another Rs. 500 crore. Technical credits would be Rs. 860 crores more than estimated because there is a temporary imbalance in trade under the rupee payment arrangements. The Revised Estimates for major subsidies exceed the Budget Estimates by Rs. 1,034 crores. The increase in food subsidies, at Rs. 250 crores, is attributable to sugar, in which the increase in issue prices to producers implemented in January 1990 was not followed by an increase in issue prices for consumers in the public distribution system. The increase in fertiliser subsidies, at Rs. 400 crores, is a consequence of the increase in the domestic prices of naphtha and the increase in the landed costs of imported fertiliser. The increase in export subsidies, at Rs. 384 crores, is because Cash Compensatory Support, given at ad valorem rates, is a function of the rupee value of exports.

11. Gross tax revenue is expected to be Re. 58,916 crores, which is Rs. 862 crores less than the budget estimates of Rs. 59,778 crores. Income tax and Corporation tax are estimated to yield Rs. 134 crores and Rs. 261 crores, respectively, more than the budget estimates, largely as a result of the post budget additional resource mobilisation during the current year. However, customs duties and excise duties are expected to yield Rs. 660 crore and Rs. 625 crores, respectively, less than the budget estimates, despite the post budget additional resource mobilisation during the current year. Non-tax revenue is expected to be Rs. 419 crore; larger Capital receipts are expected to register an improvement of Rs. 4,399 crores, of which Rs. 2,500 crores will be from small savings collections.

12. Revised estimates of total receipts and total expenditure show that the current year is likely to end with a budget deficit of Rs. 10,772 crores compared to Rs. 7,206 crores estimated at the time of the budget. I would like to stress that, but for measures implemented in the past three months, in the spheres of both revenue and expenditure, this budget deficit would have been significantly higher. It is a matter of concern that the additional expenditures have to be met from additional borrowing, thus pushing up the estimated fiscal deficit in the current year to Rs. 43,331 crores from Rs. 36,795 crores envisaged in the budget. The increase in the fiscal deficit is, to some extent, beyond the control of the Government due to the autonomous buoyancy in small savings collections, as a result of which the provision for loans to State Governments against small savings collections has gone up by Rs. 2,270 crores in the revised estimates. Were it not for this factor the fiscal deficit, now estimated at 8.59 per cent of GDP, would have been 8.14 per cent of GDP.

BUDGET ESTIMATES FOR 1991-92

13. I shall now turn to the interim budget for 1991-92, which is being presented for the purpose of a Vote-on-Account to enable Government to meet essential expenditure during the first four months of the next financial year. The Demand for Grants and the Annual Financial Statement, which are for the entire financial year, would be revised as necessary and finalised at the time of presentation of the regular budget.

14. At this stage, budget support for the Central Plan outlay in 1991-92 is placed at Rs. 18,550 crores, while Central assistance for the plans of States and Union Territories is placed at Rs. 14,710 crores for 1991-92. On this basis, the outlay for the Central Plan would be Rs. 42,148 crores, while the plan outlay of States and Union Territories, including special area programmes, would be about Rs. 29,300 crores. It has been my endeavour to provide the maximum possible support to programmes for the poor and the weaker sections of society, specially in the rural areas.

15. We have stressed economy and austerity in non-plan expenditure in order to maintain levels of investment and sustain the momentum of growth. Thus, I have taken great care to ensure that non-plan expenditure is kept at the barest minimum level next year. In absolute terms, the total non-plan expenditure would increase by a marginal amount from Rs. 76,761 crores in the current year to Rs. 76,907 crores next year.

16. No provision has been made for additional instalments of dearness allowance that may become payable next year. I am requesting all Ministries and Departments to absorb this additional liability within their budgeted outlay by effecting suitable economies. The provision for payment of loans to States, on account of their share of small savings, placed at Rs. 4,500 crores next year against Rs. 6,770 crores in the Revised Estimates for the current year. This reduction is due to the proposed transfer of the National Savings Scheme to the Bharat Bachat Bank, to be set up soon.

17. The provision for defence expenditure during the next year is placed at Rs. 16,850 crores. To meet the obligation of the Government under the scheme of rural debt relief introduced this year, a provision of Rs. 1,500 crores is also being made for the next year.

18. In our quest for fiscal consolidation, it is essential to rationalise expenditure on subsidies. As a first step in this direction, I propose to reduce the budgetary allocations for the major subsidies on exports, fertilisers and food from Rs. 9,550 crores in the Revised Estimates for 1990-91 to Rs. 8,616 crores in the Budget Estimates for 1991-92. In my view, a better targeting of subsidies for the poor and the needy, combined with an improvement in management, should make it possible to attain the desired objectives within these allocations.

19. In the sphere of receipts, at the existing rates of taxation, gross tax revenue is estimated at Rs. 65,354 crores next year, compared to the revised estimate of Rs. 58,916 crores in the current year. The payments to States of their shares taxes is placed at Rs. 15,900 crores next year as against Rs. 14,535 crores in the current year. Thus, the next revenue receipts of the Centre, including non-tax revenue, are estimated to increase from Rs. 57,381 crores in 1990-91 to Rs. 63,584 crores in 1991-92. Under capital receipts, market borrowings are placed at Rs. 7,500 crores next year which is lower than Rs. 8,000 crores in the current year. Budgetary receipts from net collections of small savings are estimated at Rs. 6,000 crores in 1991-92 as compared with Rs. 8,000 crores in 1990-91 on account of the transfer of the National Savings Scheme to the new Bharat Bachat Bank, proposed to be set up. External assistance excluding grants but net of repayments is expected to be Rs. 4,000 crores in the next year as against Rs. 3,984 crores in the current year.

20. It has been decided that Government would disinvest upto 20 per cent of its equity in selected public sector undertakings, in favour of mutual funds and financial or investment institutions in the public sector. This disinvestment, which would broad-base the equity, improve management and enhance the availability of resources for these enterprises, is also expected to yield Rs. 2,500 crores to the exchequer in 1991-92. The modalities and details of implementing this decision, which are being worked out, would be announced separately.

21. Taking into account the other variations in receipts and expenditure, total receipts at the 1990-91 rates of taxation are estimated at

Rs. 1,00,190 crores, while total expenditure is estimated at Rs. 1,10,167 crores, so that the budget deficit, without additional resource mobilisation, would be Rs. 9,977 crores.

22. The increase in the budgetary provisions for plan expenditure and other important categories of expenditure are related to, and depend upon, the magnitude of total receipts that emerges in the regular budget. The interim period, before the presentation of the regular budget, would be utilised for a close scrutiny and review of all these expenditure provisions, so as to ensure that the fiscal deficit of the Central Government is about 6.5 per cent of GDP in 1991-92. The increases in provisions, wherever these are substantial, could not therefore be taken fully into account in determining the provisions for which the Vote-on-Accounts is to be sought, except in respect of items such as interest payments, salary or pension payments and statutory grants to State Governments. I am requesting all Ministries, Departments and Public Sector Undertakings of the Central Government not to take up any new schemes and not to enter into any fresh major commitments during this period. All Ministries and Departments will also be advised to observe utmost economy in expenditure and austerity would continue to be the watchword of the Government.

23. I propose to introduce a Finance Bill which seeks to continue the existing rates of Income tax in the financial year 1991-92. There is no change in the rates of Customs and Central Excise duties. However, provision has been made in the Finance Bill for the continuance of the auxiliary duties of Customs and special duties of Excise at the existing rates in the next financial year.

SMT. JANAKI KATHPALIA,
O.S.D. (Budget)